

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या- 35/XXVII(9)/2011/स्टाम्प-20/2010
देहरादून: दिनांक 24 जनवरी, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त जारी की गई पूर्व अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तरण करते हुए, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 45 के अधीन परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित विभाजन विलेखों में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर में निम्नानुसार कमी करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. नगरपालिका, महानगर पालिका, केन्टोनमेन्ट एवं औद्योगिक विकास क्षेत्र की सीमान्तर्गत दस करोड़ रु० मूल्य तक के विभाजन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत तथा अधिकतम रु० एक लाख तथा दस करोड़ रु० मूल्य से अधिक के विभाजन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत तथा अधिकतम रु० तीन लाख।
2. नगरपालिका, महानगर पालिका, केन्टोनमेन्ट एवं औद्योगिक विकास क्षेत्र की सीमा से बाहर की सम्पत्ति से सम्बन्धित विभाजन विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दर चार प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम रु० पच्चीस हजार।

स्पष्टीकरण:- परिवार का तात्पर्य इस प्रयोजन हेतु पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन तथा नाती-पोतों से हैं।

/
(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या- 35 (1)/XXVII(9)/2011/स्टाम्प-20/2010, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन। **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड !**
- 2- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
- 3- महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 35/XXVII (9)/2011/Stamp-20/2010, Dehradun, Dated 24 January, 2011 for general information.

Government of Uttarakhand
VITTA ANUBHAG-9
No. 35/XXVII(9)/Stamp-20/2010
Dated : Dehradun, 24 January, 2011

Notification

In exercise of the powers conferred by clause (a) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttarakhand, read with section 21 of the General clauses Act, 1897 (Central Act no. 10 of 1897) and in partial modification of all previous notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to permit reduction of stamp duty under Article 45 of Schedule 1-B of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899) on instruments relating to the partition of properties among family members at the rates specified below:-

- 1- within the limit of municipality, municipal corporation, cantonment and industrial development area, on instruments valued up to rupees ten crores, the rates of stamp duty reduced from four percent to one percent maximum rupees one lac. and on the instruments valued more than rupees ten crores, the rates of stamp duty reduced from four percent to one percent maximum two rupees three lac.
- 2- Beyond the limits of municipality, municipal corporation, cantonment and industrial development area, the rates of stamp duty reduced from four percent two 0.25 percent. maximum rupees twenty five thousand

Explanation:- Family for this purpose means father, mother, husband, wife, son, daughter, daughter in law, brothers, sisters and grand children.


(Radha Raturi)
Secretary